

# EXAM GENIUS

Presents

# ***WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE***

**In BILINGUAL**

**7 - 13 JUNE 2026**

India's No. 1 Platform for UPSC  
| SSC | BANK RAILWAY Exam



 UPSC

 SSC

 BANK

 RAILWAY

 STATE EXAMS

**Ques: According to the RBI draft amendment directions, what is the current bulk deposit threshold for Scheduled Commercial Banks (SCBs) and Small Finance Banks (SFBs)?**

**प्रश्न: RBI के मसौदा संशोधन निर्देशों के अनुसार Scheduled Commercial Banks (SCBs) और Small Finance Banks (SFBs) के लिए वर्तमान बल्क डिपॉजिट सीमा क्या है?**

- A) ₹15 lakh and above / ₹15 लाख और उससे अधिक
- B) ₹50 lakh and above / ₹50 लाख और उससे अधिक
- C) ₹1 crore and above / ₹1 करोड़ और उससे अधिक
- D) ₹3 crore and above / ₹3 करोड़ और उससे अधिक
- E) ₹5 crore and above / ₹5 करोड़ और उससे अधिक

**Answer: Option D**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) has issued draft amendment directions to provide banks greater flexibility in pricing rupee bulk deposits.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को रुपये के बल्क डिपॉजिट की ब्याज दर तय करने में अधिक लचीलापन देने हेतु मसौदा संशोधन निर्देश जारी किए हैं।
- The proposal seeks to balance flexibility for banks with greater transparency and uniformity in the disclosure of deposit interest rates.
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य बैंकों को लचीलापन प्रदान करने के साथ-साथ जमा ब्याज दरों के प्रकटीकरण में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
- Banks will be required to publish their schedule of deposit interest rates on their websites before the commencement of the business day.
- बैंकों को कार्य दिवस शुरू होने से पहले अपनी जमा ब्याज दरों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी।
- RBI has proposed allowing differential interest rates on bulk deposits based on applicable run-off rates under the Liquidity Coverage Ratio (LCR) framework.

- आरबीआई ने तरलता कवरेज अनुपात (LCR) ढांचे के तहत लागू रन-ऑफ दरों के आधार पर बल्क डिपॉजिट पर अलग-अलग ब्याज दरें देने का प्रस्ताव रखा है।
- Under the existing RBI framework, a single rupee term deposit of ₹3 crore and above is classified as a bulk deposit for Scheduled Commercial Banks (SCBs) and Small Finance Banks (SFBs).
- मौजूदा आरबीआई ढांचे के अनुसार, ₹3 करोड़ या उससे अधिक की एकल रुपये की सावधि जमा (Term Deposit) को Scheduled Commercial Banks (SCBs) और Small Finance Banks (SFBs) के लिए बल्क डिपॉजिट माना जाता है।
- The move aims to improve deposit mobilisation while maintaining regulatory transparency and market discipline.
- इस कदम का उद्देश्य नियामकीय पारदर्शिता और बाजार अनुशासन बनाए रखते हुए जमा संग्रहण को बेहतर बनाना है।
- RBI has invited comments and feedback from regulated entities and stakeholders on the draft directions till 20 June 2026.
- आरबीआई ने मसौदा निर्देशों पर विनियमित संस्थाओं और हितधारकों से 20 जून 2026 तक सुझाव एवं प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।
- Current bulk deposit thresholds vary across different categories of banks.
- वर्तमान में बल्क डिपॉजिट की सीमा विभिन्न प्रकार के बैंकों के लिए अलग-अलग निर्धारित है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

RBI Deputy Governors

- Swaminathan Janakiraman
- स्वामीनाथन जानकीरमन
- Dr. Poonam Gupta
- डॉ. पूनम गुप्ता
- Shirish Chandra Murmu
- शिरीष चंद्र मुर्मू
- Rohit Jain
- रोहित जैन

**Ques: Which organisation has been recognised by RBI as the Self-Regulatory Organisation (SRO) for the Account Aggregator ecosystem?**

**प्रश्न: अकाउंट एग्रीगेटर (AA) इकोसिस्टम के लिए RBI द्वारा किस संगठन को स्व-नियामक संगठन (SRO) के रूप में मान्यता दी गई है?**

- A. NPCI / एनपीसीआई
- B. Sahamati Foundation / सहमति फाउंडेशन
- C. SIDBI / सिडबी
- D. NABARD / नाबार्ड
- E. NASSCOM / नैसकॉम

**Answer: Option B**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) has recognised Sahamati Foundation as the Self-Regulatory Organisation (SRO) for the Account Aggregator (AA) ecosystem.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अकाउंट एग्रीगेटर (AA) इकोसिस्टम के लिए सहमति फाउंडेशन को स्व-नियामक संगठन (SRO) के रूप में मान्यता प्रदान की है।
- Sahamati Foundation was launched in 2019 as a non-profit organisation to promote the Account Aggregator ecosystem.
- सहमति फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2019 में अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी।
- The organisation is led by CEO BG Mahesh.
- संगठन का नेतृत्व CEO बी.जी. महेश कर रहे हैं।
- Earlier this year, Sahamati raised ₹50 crore funding from more than 30 financial sector entities.
- इस वर्ष की शुरुआत में सहमति ने 30 से अधिक वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं से ₹50 करोड़ की फंडिंग जुटाई।
- Key contributors included SBI, ICICI Bank, HDFC Bank, Tata Capital, Bajaj Finserv, Zerodha, Dhan and others.
- प्रमुख निवेशकों में SBI, ICICI Bank, HDFC Bank, Tata Capital, Bajaj Finserv, Zerodha, Dhan आदि शामिल हैं।

- RBI has prescribed five major conditions for recognition as an SRO-AA.
- RBI ने SRO-AA के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पाँच प्रमुख शर्तें निर्धारित की हैं।
- The applicant must be a not-for-profit entity registered as a Section 8 company under the Companies Act, 2013.
- आवेदक संस्था को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत गैर-लाभकारी संस्था होना आवश्यक है।
- The entity must achieve and maintain a minimum net worth of ₹2 crore within one year of recognition or before commencing operations.
- संस्था को मान्यता मिलने के एक वर्ष के भीतर या संचालन शुरू करने से पहले ₹2 करोड़ की न्यूनतम नेटवर्थ बनाए रखनी होगी।
- No single shareholder can hold 10% or more stake, directly or indirectly, ensuring diversified ownership.
- किसी भी एक शेयरधारक के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10% या उससे अधिक हिस्सेदारी नहीं हो सकती, जिससे स्वामित्व का विविधीकरण सुनिश्चित हो।
- The SRO-AA must represent NBFC-AAs, FIPs and FI-Us and maintain at least 25 unique entities each from FIPs and FI-Us as members.
- SRO-AA को NBFC-AA, FIP और FI-U का प्रतिनिधित्व करना होगा तथा FIP और FI-U श्रेणियों से कम से कम 25-25 सदस्य संस्थाएँ बनाए रखनी होंगी।
- At least one-third of the board, including the chairperson, must consist of independent directors with no active association with AA ecosystem participants.
- बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई सदस्य, जिनमें अध्यक्ष भी शामिल हों, स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए जिनका AA इकोसिस्टम के प्रतिभागियों से सक्रिय संबंध न हो।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

### **Reserve Bank of India (RBI)**

- Established – 1 April 1935
- स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- Nationalised – 1 January 1949
- राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- Governor – Sanjay Malhotra

- गवर्नर – संजय मल्होत्रा
- First Governor – Sir Osborne Smith
- प्रथम गवर्नर – सर ऑसबोर्न स्मिथ
- First Indian Governor – C. D. Deshmukh
- प्रथम भारतीय गवर्नर – सी. डी. देशमुख

### **Sahamati Foundation**

- Founded – 2019
- स्थापना – 2019
- Nature – Not-for-Profit Organisation
- स्वरूप – गैर-लाभकारी संगठन
- Purpose – Promotion of the Account Aggregator Ecosystem
- उद्देश्य – अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना
- CEO – BG Mahesh
- सीईओ – बी.जी. महेश

---

**Ques: Which country recorded the highest FPI equity outflow among major emerging markets in 2026?**

**प्रश्न: 2026 में प्रमुख उभरते बाजारों में सबसे अधिक एफपीआई (FPI) इक्विटी निकासी किस देश में दर्ज की गई?**

- A) India / भारत
- B) Indonesia / इंडोनेशिया
- C) South Korea / दक्षिण कोरिया
- D) Vietnam / वियतनाम
- E) Malaysia / मलेशिया

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- South Korea and India have witnessed the highest Foreign Portfolio Investor (FPI) equity outflows among major emerging markets in 2026.
- वर्ष 2026 में प्रमुख उभरते बाजारों में दक्षिण कोरिया और भारत से सबसे अधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) इक्विटी निकासी दर्ज की गई है।
- South Korea recorded the largest FPI equity outflow of about \$69.6 billion year-to-date (YTD) in 2026.
- दक्षिण कोरिया में 2026 में अब तक लगभग 69.6 बिलियन डॉलर की एफपीआई इक्विटी निकासी दर्ज की गई, जो सबसे अधिक है।
- India witnessed net FPI equity outflows of around \$27.2 billion during the same period.
- भारत में इसी अवधि के दौरान लगभग 27.2 बिलियन डॉलर की शुद्ध एफपीआई इक्विटी निकासी दर्ज की गई।
- The outflows have been attributed to global uncertainty, profit-booking by investors, and shifting investments toward perceived safe-haven markets.
- इन निकासियों का कारण वैश्विक अनिश्चितता, निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली (Profit Booking) तथा सुरक्षित माने जाने वाले बाजारों की ओर निवेश का स्थानांतरण बताया गया है।
- Despite equity outflows, India continued to attract foreign investments into its debt market.
- इक्विटी से निकासी के बावजूद भारत के ऋण (Debt) बाजार में विदेशी निवेश जारी रहा।
- India received net debt inflows of over \$1.2 billion in 2026, reflecting investor confidence in fixed-income assets.
- भारत को 2026 में 1.2 बिलियन डॉलर से अधिक का शुद्ध ऋण निवेश प्राप्त हुआ, जो निश्चित आय (Fixed Income) परिसंपत्तियों में निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है।
- To attract foreign capital, the Government of India reduced withholding tax on foreign debt investments and removed capital gains tax on certain government securities.
- विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने विदेशी ऋण निवेश पर विदहोलिडिंग टैक्स कम किया तथा कुछ सरकारी प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) समाप्त किया।
- The trend highlights a divergence between investor sentiment toward equity and debt markets in emerging economies.
- यह प्रवृत्ति उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी और ऋण बाजारों के प्रति निवेशकों की

अलग-अलग धारणा को दर्शाती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी

- South Korea Capital – Seoul
- दक्षिण कोरिया की राजधानी – सियोल
- South Korea Currency – South Korean Won (KRW)
- दक्षिण कोरिया की मुद्रा – साउथ कोरियन वॉन (KRW)
- KOSPI – Benchmark Stock Market Index of South Korea
- KOSPI – दक्षिण कोरिया का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक
- Securities and Exchange Board of India Headquarters – Mumbai
- सेबी मुख्यालय – मुंबई
- FPI Full Form – Foreign Portfolio Investor
- FPI का पूर्ण रूप – विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक

---

**Ques: What was India's estimated real GDP growth rate for FY 2025-26 as per the provisional estimates released by MoSPI?**

**प्रश्न: MoSPI द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या रही?**

- A) 7.1%
- B) 7.4%
- C) 7.6%
- D) 7.7%
- E) 7.8%

**Answer: Option D**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- India's real GDP growth for FY 2025-26 has been estimated at 7.7%, compared to 7.1% in FY 2024-25.
- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान

है, जो 2024-25 के 7.1% से अधिक है।

- The provisional estimates were released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI).
- यह अनंतिम अनुमान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी किए गए हैं।
- The estimated growth rate of 7.7% is slightly higher than the 7.6% projection made in February 2026.
- 7.7% की अनुमानित वृद्धि दर फरवरी 2026 में किए गए 7.6% के अनुमान से थोड़ी अधिक है।
- India's GDP growth in the fourth quarter (Q4) of FY 2025-26 stood at 7.8%.
- वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (Q4) में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही।
- This growth performance keeps India among the fastest-growing major economies in the world.
- यह प्रदर्शन भारत को विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनाए रखता है।
- Prime Minister Narendra Modi stated that these figures reflect the success of economic reforms and the hard work of 140 crore Indians.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये आंकड़े आर्थिक सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत को दर्शाते हैं।
- Finance Minister Nirmala Sitharaman highlighted strong growth in manufacturing, trade, transport, communication, financial and professional services sectors.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिर्माण, व्यापार, परिवहन, संचार, वित्तीय एवं पेशेवर सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि को रेखांकित किया।
- The higher GDP growth reflects continued economic resilience, rising investments and strong domestic demand.
- उच्च जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक मजबूती, बढ़ते निवेश और मजबूत घरेलू मांग को दर्शाती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

### **Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI)**

- Established – 15 October 1999
- स्थापना – 15 अक्टूबर 1999

- Headquarters – New Delhi
- मुख्यालय – नई दिल्ली
- Responsible for national statistical data and GDP estimates
- राष्ट्रीय सांख्यिकीय आंकड़ों एवं जीडीपी अनुमानों के लिए उत्तरदायी
- Base Year of GDP Calculation (Current Series) – 2022-23
- जीडीपी गणना का आधार वर्ष (वर्तमान श्रृंखला) – 2022-23

---

**Ques : International Finance Corporation (IFC) has committed USD 50 million to which company to promote green hydrogen projects in India?**

**प्रश्न: भारत में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए IFC ने 50 मिलियन डॉलर का निवेश किस कंपनी में किया है?**

- A) Avaada Energy / अवाडा एनर्जी
- B) ReNew Power / रिन्यू पावर
- C) Hygenco Green Energies / हाइजेको ग्रीन एनर्जीज़
- D) ACME Cleantech / एसीएमई क्लीनटेक
- E) NTPC Green Energy / एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- International Finance Corporation (IFC), the private-sector arm of the World Bank Group, has committed USD 50 million to Hygenco Green Energies.
- विश्व बैंक समूह की निजी क्षेत्र निवेश इकाई IFC ने Hygenco Green Energies में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की घोषणा की है।
- IFC, Siemens Financial Services, Clean Technology Fund, Frontier Opportunities Fund and Fullerton Carbon Action Fund together signed an agreement for a total investment of USD 105 million.
- IFC, Siemens Financial Services, Clean Technology Fund, Frontier Opportunities Fund और Fullerton Carbon Action Fund ने मिलकर कुल 105

मिलियन डॉलर के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- The investment will support the development of multiple green hydrogen and green ammonia projects across India.
- यह निवेश भारत में कई ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं के विकास में सहायता करेगा।
- Hygenco aims to expand the supply of green hydrogen to industries such as steel, refineries, fertilizers and other hard-to-abate sectors.
- Hygenco का उद्देश्य इस्पात, रिफाइनरी, उर्वरक तथा अन्य कठिन-डीकार्बोनाइजेशन वाले क्षेत्रों को ग्रीन हाइड्रोजन उपलब्ध कराना है।
- The initiative supports India's National Green Hydrogen Mission and the country's clean energy transition goals.
- यह पहल भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को समर्थन देती है।
- The company is expected to create more than 1,000 direct jobs over the next five years and generate significant indirect employment opportunities.
- कंपनी अगले पांच वर्षों में 1,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित करेगी।
- The partnership aims to scale up the "Hydrogen-as-a-Service" model and strengthen India's green hydrogen value chain.
- यह साझेदारी "Hydrogen-as-a-Service" मॉडल को बढ़ावा देने तथा भारत की ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- International Finance Corporation (IFC) Established – 1956
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) की स्थापना – 1956
- Headquarters – Washington D.C., USA
- मुख्यालय – वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका
- Parent Organization – World Bank Group
- मूल संगठन – विश्व बैंक समूह
- Managing Director of IFC – Makhtar Diop
- IFC के प्रबंध निदेशक – मख्तर डियोप
- National Green Hydrogen Mission Launched – January 2023
- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत – जनवरी 2023

- Target under National Green Hydrogen Mission – 5 Million Metric Tonnes (MMT) of Green Hydrogen annually by 2030
  - राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य – 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन
- 

**Ques: According to the World Inequality Lab report, by around which year is India projected to surpass China in its share of global GDP measured in PPP terms?**

**प्रश्न: World Inequality Lab की रिपोर्ट के अनुसार PPP के आधार पर वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी के मामले में भारत लगभग किस वर्ष चीन से आगे निकल सकता है?**

- A) 2040
- B) 2050
- C) 2060
- D) 2075
- E) 2100

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- India is projected to surpass China in terms of its share of global GDP measured in Purchasing Power Parity (PPP) by around 2060.
- क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी के मामले में भारत के वर्ष 2060 तक चीन से आगे निकलने का अनुमान है।
- The projection has been made in the Global Justice Report prepared by researchers associated with the World Inequality Lab.
- यह अनुमान World Inequality Lab से जुड़े शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की गई Global Justice Report में लगाया गया है।
- China's share in global GDP is currently around 20% in PPP terms but is expected to decline during the second half of the 21st century due to demographic changes.
- वर्तमान में PPP के आधार पर वैश्विक जीडीपी में चीन की हिस्सेदारी लगभग 20% है,

लेकिन जनसंख्या में बदलाव के कारण 21वीं सदी के उत्तरार्ध में इसके घटने का अनुमान है।

- India's share in world GDP is currently about 8% in PPP terms and is projected to increase steadily over the coming decades.
- वर्तमान में PPP के आधार पर वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8% है और आने वाले दशकों में इसके लगातार बढ़ने का अनुमान है।
- The report attributes India's rise to sustained economic growth, demographic advantages, and increased investment in human capital.
- रिपोर्ट के अनुसार भारत की बढ़ती हिस्सेदारी का कारण निरंतर आर्थिक वृद्धि, जनसांख्यिकीय लाभ तथा मानव पूंजी में निवेश है।
- The report suggests that the 21st century will witness a multipolar global economy rather than dominance by a single country.
- रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी में वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुध्रुवीय (Multipolar) होगी, जिसमें किसी एक देश का प्रभुत्व नहीं रहेगा।
- India is expected to emerge as one of the leading economic powers of the world during the coming decades.
- आने वाले दशकों में भारत के विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में उभरने की संभावना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- International Monetary Fund Headquarters – Washington D.C., USA
  - IMF मुख्यालय – वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका
  - World Bank Headquarters – Washington D.C., USA
  - विश्व बैंक मुख्यालय – वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका
  - India's Current Rank in GDP (PPP) – 3rd Largest Economy
  - PPP के आधार पर भारत की वर्तमान रैंक – तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
  - Purchasing Power Parity (PPP) compares the relative purchasing power of currencies across countries.
  - क्रय शक्ति समता (PPP) विभिन्न देशों की मुद्राओं की वास्तविक क्रय शक्ति की तुलना करने की एक पद्धति है।
-

**Ques: According to the latest outlook released by the OECD, what is India's projected GDP growth rate for 2026–27?**

**प्रश्न: OECD द्वारा जारी नवीनतम आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार, वर्ष 2026–27 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी है?**

- A) 5.8%
- B) 6.0%
- C) 6.3%
- D) 6.8%
- E) 7.0%

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- According to the latest outlook released by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), India's economy is projected to grow by 6.3% in 2026–27.
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा जारी नवीनतम आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार, वर्ष 2026–27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
- The OECD has also projected India's GDP growth at 6.4% for 2027–28.
- OECD ने वर्ष 2027–28 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान भी व्यक्त किया है।
- The forecast highlights India's position among the fastest-growing major economies in the world.
- यह अनुमान भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में दर्शाता है।
- Strong domestic demand, investment activity and ongoing economic reforms are expected to support growth in the coming years.
- मजबूत घरेलू मांग, निवेश गतिविधियों और जारी आर्थिक सुधारों से आगामी वर्षों में विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
- OECD regularly publishes economic outlook reports assessing global and country-specific growth prospects.

- OECD समय-समय पर वैश्विक और देश-विशिष्ट आर्थिक संभावनाओं का आकलन करने वाली आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- OECD Full Form – Organisation for Economic Co-operation and Development
- OECD का पूर्ण रूप – आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
- Founded – 30 September 1961
- स्थापना – 30 सितंबर 1961
- Headquarters – Paris
- मुख्यालय – पेरिस, फ्रांस
- Membership – 38 Countries
- सदस्यता – 38 देश
- Secretary-General – Mathias Cormann
- महासचिव – मैथियास कॉर्मन

---

**Ques: Under the RBI's latest reforms, which Government Securities have been newly designated as 'specified securities' under the Fully Accessible Route (FAR)?**

**प्रश्न: आरबीआई के नवीनतम सुधारों के तहत Fully Accessible Route (FAR) में किन सरकारी प्रतिभूतियों को 'निर्दिष्ट प्रतिभूतियां' घोषित किया गया है?**

- A) 5-year and 10-year G-Secs only / केवल 5 वर्ष और 10 वर्ष की जी-सेक्स
- B) 7-year and 20-year G-Secs only / केवल 7 वर्ष और 20 वर्ष की जी-सेक्स
- C) 15-year, 30-year and 40-year G-Secs / 15 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष की जी-सेक्स
- D) All Government Securities / सभी सरकारी प्रतिभूतियां
- E) Treasury Bills only / केवल ट्रेजरी बिल

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) has announced major reforms to simplify and expand Foreign Portfolio Investor (FPI) investments in Government Securities (G-Secs).
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के निवेश को सरल और विस्तारित करने हेतु महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है।
- Under the General Route, RBI has removed short-term investment limits, concentration limits and individual security-wise limits.
- सामान्य मार्ग (General Route) के तहत आरबीआई ने अल्पकालिक निवेश सीमा, एकाग्रता सीमा तथा व्यक्तिगत प्रतिभूति-आधारित सीमाओं को समाप्त कर दिया है।
- The existing “General” and “Long-term” investment categories have been merged into a single limit for Government Securities and State Government Securities.
- मौजूदा “General” और “Long-term” निवेश श्रेणियों को सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एकल सीमा में विलय कर दिया गया है।
- RBI has designated all new issuances of 15-year, 30-year and 40-year Government Securities as “specified securities” under the Fully Accessible Route (FAR).
- आरबीआई ने 15 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष की अवधि वाली सभी नई सरकारी प्रतिभूतियों को Fully Accessible Route (FAR) के तहत “निर्दिष्ट प्रतिभूतियां” घोषित किया है।
- All new Sovereign Green Bond issuances in 5-year, 7-year, 10-year, 15-year, 30-year and 40-year tenors will also qualify as specified securities under FAR.
- 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष की अवधि वाले सभी नए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी FAR के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में शामिल होंगे।
- Despite these relaxations, the overall investment cap remains unchanged at 6% of outstanding Central Government Securities and 2% of State Government Securities.
- इन रियायतों के बावजूद कुल निवेश सीमा अपरिवर्तित रहेगी, जो केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के लिए 6% तथा राज्य सरकारी प्रतिभूतियों के लिए 2% निर्धारित है।
- The directions have been issued under Sections 10(4) and 11(1) of the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999.
- ये निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 की धारा 10(4) और 11(1) के

तहत जारी किए गए हैं।

- The reforms aim to attract greater foreign investment and improve liquidity in India's government bond market.
- इन सुधारों का उद्देश्य भारत के सरकारी बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेश बढ़ाना और तरलता में सुधार करना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

### **Monetary Policy Committee (MPC)**

- Total Members – 6
- कुल सदस्य – 6
- Composition – 3 RBI officials and 3 members nominated by the Central Government
- संरचना – 3 RBI अधिकारी और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य

### **Fully Accessible Route (FAR)**

- Introduced – 2020
- शुरुआत – 2020
- Purpose – To allow non-resident investors unrestricted investment in specified Government Securities
- उद्देश्य – गैर-निवासी निवेशकों को निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में बिना सीमा निवेश की अनुमति देना

---

**Ques: The Government has extended the tenure of RBI Deputy Governor Swaminathan Janakiraman for another two years. He was originally appointed as RBI Deputy Governor in which year?**

**प्रश्न: सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जनकीरमन का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ा दिया है। उन्हें मूल रूप से RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था?**

- A) 2021
- B) 2022
- C) 2023
- D) 2024
- E) 2025

## Answer: Option C

---

### Explanation | व्याख्या:

- The Central Government has extended the tenure of RBI Deputy Governor Swaminathan Janakiraman for another two years.
- केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जनकीरमन का कार्यकाल दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।
- He was originally appointed as Deputy Governor of the Reserve Bank of India in June 2023 for a three-year term.
- उन्हें जून 2023 में तीन वर्ष की अवधि के लिए RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था।
- The reappointment will take effect from 26 June 2026.
- उनकी पुनर्नियुक्ति 26 जून 2026 से प्रभावी होगी।
- Prior to joining RBI, Swaminathan Janakiraman held several senior positions in the State Bank of India (SBI).
- RBI में शामिल होने से पहले स्वामीनाथन जनकीरमन भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में कई वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं।
- As Deputy Governor, he is associated with banking regulation, supervision and financial sector oversight.
- डिप्टी गवर्नर के रूप में वे बैंकिंग विनियमन, पर्यवेक्षण तथा वित्तीय क्षेत्र की निगरानी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व संभालते हैं।

### Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Reserve Bank of India (RBI) Established – 1 April 1935
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- RBI Nationalised – 1 January 1949
- RBI का राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949
- Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- Governor – Sanjay Malhotra
- गवर्नर – संजय मल्होत्रा

- Deputy Governors of RBI – 4
- RBI के डिप्टी गवर्नरों की संख्या – 4
- First Governor – Sir Osborne Smith
- प्रथम गवर्नर – सर ऑसबोर्न स्मिथ
- First Indian Governor – C. D. Deshmukh
- प्रथम भारतीय गवर्नर – सी. डी. देशमुख

---

**Ques: The Asian Development Bank (ADB) and Standard Chartered Bank signed agreements to strengthen trade finance and supply chain finance in India through arrangements structured via which financial hub?**

**प्रश्न: एशियाई विकास बैंक (ADB) और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भारत में व्यापार वित्त एवं आपूर्ति श्रृंखला वित्त को मजबूत करने के लिए जिस व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए, उसे किस वित्तीय केंद्र के माध्यम से संरचित किया गया है?**

- A) International Financial Services Centre, Mumbai / अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, मुंबई
- B) GIFT City / गिफ्ट सिटी
- C) Hyderabad Financial District / हैदराबाद वित्तीय जिला
- D) Bengaluru FinTech Hub / बेंगलुरु फिनटेक हब
- E) IFSC Chennai / आईएफएससी चेन्नई

**Answer: Option B**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The Asian Development Bank (ADB) and Standard Chartered Bank signed two agreements to strengthen trade finance and supply chain finance in India.
- एशियाई विकास बैंक (ADB) और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भारत में व्यापार वित्त (Trade Finance) और आपूर्ति श्रृंखला वित्त (Supply Chain Finance) को मजबूत करने के लिए दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

- The agreements involve risk-sharing arrangements covering both US Dollar (USD) and Indian Rupee (INR) transactions.
- इन समझौतों में अमेरिकी डॉलर (USD) और भारतीय रुपये (INR) दोनों में होने वाले लेन-देन के लिए जोखिम-साझाकरण (Risk-Sharing) व्यवस्था शामिल है।
- The arrangement has been structured through GIFT City (Gujarat International Finance Tec-City).
- यह व्यवस्था GIFT City (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) के माध्यम से संरचित की गई है।
- The partnership aims to improve access to finance for businesses and strengthen cross-border trade activities.
- इस साझेदारी का उद्देश्य व्यवसायों के लिए वित्तीय पहुंच बढ़ाना और सीमा-पार व्यापार गतिविधियों को मजबूत करना है।
- Risk-sharing mechanisms help financial institutions expand lending while managing exposure to potential risks.
- जोखिम-साझाकरण तंत्र वित्तीय संस्थानों को संभावित जोखिमों का प्रबंधन करते हुए ऋण उपलब्धता बढ़ाने में मदद करता है।
- The initiative is expected to support India's growing trade ecosystem and supply chain resilience.
- यह पहल भारत के बढ़ते व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को समर्थन प्रदान करेगी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Asian Development Bank (ADB) Formation – 19 December 1966
- एशियाई विकास बैंक (ADB) की स्थापना – 19 दिसंबर 1966
- Headquarters – Manila
- मुख्यालय – मनीला, फिलीपींस
- Members – 69 Countries
- सदस्य देश – 69
- President – Masato Kanda
- अध्यक्ष – मसातो कांडा
- 69th Member of ADB – Israel
- ADB का 69वां सदस्य – इज़राइल
- GIFT Full Form – Gujarat International Finance Tec-City

- GIFT का पूर्ण रूप – गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी
- Location of GIFT City – Gandhinagar, Gujarat
- गिफ्ट सिटी का स्थान – गांधीनगर, गुजरात

---

**Ques: Who has been appointed as the Executive Director (ED) at the World Bank by the Appointments Committee of the Cabinet (ACC)?**

**प्रश्न: मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक (Executive Director) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?**

- A) Parameswaran Iyer / परमेश्वरन अय्यर
- B) Neelkanth Mishra / नीलकंठ मिश्रा
- C) Rajiv Kumar / राजीव कुमार
- D) Anantha Nageswaran / अनंता नागेश्वरन
- E) Subhash Chandra Garg / सुभाष चंद्र गर्ग

**Answer: Option B**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The Appointments Committee of the Cabinet (ACC) has approved the appointment of Neelkanth Mishra as Executive Director (ED) at the World Bank.
- मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (ACC) ने Neelkanth Mishra की विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक (Executive Director) के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है।
- He will be based at the World Bank Headquarters in Washington, D.C., USA.
- वे अमेरिका के Washington, D.C. स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में कार्य करेंगे।
- Neelkanth Mishra will succeed Parameswaran Iyer in this position.
- नीलकंठ मिश्रा इस पद पर Parameswaran Iyer का स्थान लेंगे।
- His tenure as Executive Director will be for a period of three years.
- कार्यकारी निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
- Prior to this appointment, he was serving as the Chief Economist at Axis

Bank.

• इस नियुक्ति से पहले वे Axis Bank में मुख्य अर्थशास्त्री (Chief Economist) के पद पर कार्यरत थे।

• Neelkanth Mishra is a well-known economist and has contributed significantly to economic research and policy discussions in India.

• नीलकंठ मिश्रा एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने भारत में आर्थिक अनुसंधान एवं नीतिगत चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- World Bank Established – 1944
- विश्व बैंक की स्थापना – 1944
- Headquarters – Washington, D.C., USA
- मुख्यालय – वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका
- World Bank President – Ajay Banga
- विश्व बैंक के अध्यक्ष – अजय बंगा
- Parent Institution – World Bank Group
- मूल संस्था – विश्व बैंक समूह

---

**Ques: The Reserve Bank of India (RBI) recently imposed a monetary penalty of ₹41.80 lakh on which bank for violating directions related to KYC and unclaimed deposits/inoperative accounts?**

**प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने KYC तथा अनक्लेम्ड डिपॉजिट/निष्क्रिय खातों से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर ₹41.80 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है?**

- A) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- C) Canara Bank / केनरा बैंक
- D) Indian Bank / इंडियन बैंक
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**Answer: Option C**

---

### Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) imposed a monetary penalty of ₹41.80 lakh on Canara Bank.
- Reserve Bank of India (RBI) ने Canara Bank पर ₹41.80 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
- The penalty was imposed for violating RBI directions related to Know Your Customer (KYC) norms and unclaimed deposits/inoperative accounts.
- यह जुर्माना KYC मानदंडों तथा अनक्लेम्ड डिपॉजिट/निष्क्रिय खातों से संबंधित RBI निर्देशों के उल्लंघन के कारण लगाया गया।
- Canara Bank failed to upload the KYC records of certain customers to the Central KYC Records Registry (CKYCR).
- केनरा बैंक कुछ ग्राहकों के KYC रिकॉर्ड को सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCR) पर अपलोड करने में विफल रहा।
- RBI observed deficiencies in regulatory compliance during its supervisory assessment.
- RBI ने अपने पर्यवेक्षी मूल्यांकन के दौरान नियामकीय अनुपालन में कमियां पाईं।
- The penalty has been imposed under the provisions of the Banking Regulation Act and does not question the validity of any customer transactions.
- यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगाया गया है और इससे ग्राहकों के किसी भी लेन-देन की वैधता प्रभावित नहीं होती।

### Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Reserve Bank of India (RBI) Established – 1 April 1935
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- RBI Headquarters – Mumbai
- RBI मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- RBI Governor – Sanjay Malhotra
- RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा
- Canara Bank Founded – 1906
- केनरा बैंक की स्थापना – 1906
- Canara Bank Headquarters – Bengaluru
- केनरा बैंक मुख्यालय – बेंगलुरु, कर्नाटक

---

**Ques: Which department is responsible for conducting the disinvestment process of NLC India's stake sale?**

**प्रश्न: एनएलसी इंडिया की हिस्सेदारी बिक्री की विनिवेश प्रक्रिया का संचालन कौन-सा विभाग कर रहा है?**

- A) Department of Financial Services (DFS) / वित्तीय सेवा विभाग
- B) Department of Public Enterprises (DPE) / लोक उद्यम विभाग
- C) Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) / निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
- D) Ministry of Coal / कोयला मंत्रालय
- E) NITI Aayog / नीति आयोग

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The Government of India will sell up to a 3% stake in NLC India through an Offer for Sale (OFS).
- भारत सरकार एनएलसी इंडिया में अपनी 3% तक हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से बेचेगी।
- The base offer includes a 2% equity stake, with an additional 1% green-shoe option if investor demand is strong.
- आधार प्रस्ताव में 2% इक्विटी हिस्सेदारी शामिल है, जबकि अधिक मांग होने पर अतिरिक्त 1% हिस्सेदारी बेचने का विकल्प रखा गया है।
- The disinvestment process is being carried out through the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM).
- विनिवेश प्रक्रिया का संचालन निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) द्वारा किया जा रहा है।
- NLC India is a public sector enterprise engaged in lignite mining and power generation.
- एनएलसी इंडिया एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो लिग्नाइट खनन एवं विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करता है।
- The Government of India has announced the OFS as part of its disinvestment programme.
- भारत सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत OFS की घोषणा की है।

- The transaction is being managed by DIPAM under the Ministry of Finance.
- इस विनिवेश प्रक्रिया का संचालन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत DIPAM द्वारा किया जा रहा है।

### Static GK | स्थैतिक जीके

- NLC India Limited Established – 1956
- एनएलसी इंडिया लिमिटेड की स्थापना – 1956
- Headquarters – Chennai, Tamil Nadu
- मुख्यालय – चेन्नई, तमिलनाडु
- Administrative Ministry – Ministry of Coal
- प्रशासनिक मंत्रालय – कोयला मंत्रालय
- Chairman & Managing Director – Prasanna Kumar Motupalli
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली
- DIPAM Established – 1999 (as Department of Disinvestment)
- डीआईपीएएम की स्थापना – 1999 (विनिवेश विभाग के रूप में)
- DIPAM Ministry – Ministry of Finance
- डीआईपीएएम मंत्रालय – वित्त मंत्रालय
- Offer for Sale (OFS) is a mechanism through which promoters can sell shares in listed companies through the stock exchange platform.
- ऑफर फॉर सेल (OFS) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से प्रमोटर स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर बेच सकते हैं।

**Ques: Which organization has committed \$50 million to Hygenco Green Energies to support the development of the green hydrogen sector in India?**  
**प्रश्न: भारत में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के लिए Hygenco Green Energies में \$50 मिलियन निवेश की प्रतिबद्धता किस संगठन ने की है?**

- A) Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक (ADB)
- B) International Finance Corporation (IFC) / अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
- C) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) / एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)
- D) New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)
- E) European Investment Bank (EIB) / यूरोपीय निवेश बैंक (EIB)

**Answer: Option B**

---

## Explanation | व्याख्या:

- International Finance Corporation (IFC) has committed \$50 million to Hygenco Green Energies.
- International Finance Corporation (IFC) ने Hygenco Green Energies में \$50 मिलियन निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
- The investment aims to support the development of the green hydrogen sector in India.
- यह निवेश भारत में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।
- IFC is the private-sector investment arm of the World Bank Group.
- IFC, World Bank Group की निजी क्षेत्र में निवेश करने वाली इकाई है।
- Along with IFC, several other investors have also invested in Hygenco Green Energies.
- IFC के साथ कई अन्य निवेशकों ने भी Hygenco Green Energies में निवेश किया है।
- These investors include Siemens Financial Services, Clean Technology Fund, Frontier Opportunities Fund and Fullerton Carbon Action Fund.
- इन निवेशकों में Siemens Financial Services, Clean Technology Fund, Frontier Opportunities Fund और Fullerton Carbon Action Fund शामिल हैं।
- Together, the investors signed an investment agreement worth \$105 million in Hygenco Green Energies.
- सभी निवेशकों ने मिलकर Hygenco Green Energies में \$105 मिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- The funding is expected to accelerate clean energy transition and green hydrogen production in India.
- यह निवेश भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को गति देने में सहायक होगा।

## Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- IFC Full Form – International Finance Corporation
- IFC का पूर्ण रूप – इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन
- Established – 1956
- स्थापना – 1956
- Parent Organization – World Bank Group
- मूल संगठन – विश्व बैंक समूह

- Headquarters – Washington, D.C.
  - मुख्यालय – वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका
- 

**Ques: Which mechanism played a major role in improving stressed asset recovery and reducing NPAs in India's banking sector?**

**प्रश्न: भारत के बैंकिंग क्षेत्र में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली बढ़ाने और NPA कम करने में किस व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?**

- A) Monetary Policy Committee (MPC) / मौद्रिक नीति समिति (MPC)
- B) Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) / दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC)
- C) Goods and Services Tax (GST) / वस्तु एवं सेवा कर (GST)
- D) PM Jan Dhan Yojana / प्रधानमंत्री जन धन योजना
- E) Unified Payments Interface (UPI) / यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

**Answer: Option B**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- India's banking sector has transformed significantly since 2014, with a sharp decline in Non-Performing Assets (NPAs), improving the overall health of banks.
- 2014 के बाद भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। एनपीए (NPA) में तेज गिरावट के कारण बैंकों की समग्र स्थिति मजबूत हुई है।
- Recoveries through the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) have strengthened bank balance sheets and increased profitability.
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के माध्यम से बेहतर वसूली ने बैंकों की बैलेंस शीट को मजबूत किया है तथा लाभप्रदता बढ़ाई है।
- Improved asset quality and stronger financial stability have restored confidence among lenders and investors.
- बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और मजबूत वित्तीय स्थिरता ने ऋणदाताओं एवं निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है।
- Robust credit growth supported by healthier banks has contributed to economic growth and development.
- मजबूत बैंकों द्वारा समर्थित ऋण वृद्धि ने आर्थिक विकास और प्रगति को गति दी है।
- Better recoveries under IBC helped reduce NPAs, strengthen bank balance

sheets, improve profitability, and restore confidence in the banking sector.

• IBC के तहत बेहतर वसूली से NPA में कमी आई, बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत हुई, लाभप्रदता बढ़ी और बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास बहाल हुआ।

## Static GK | स्थैतिक जीके

- Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) – 2016
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) – 2016
- Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) – Regulator under IBC
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) – IBC का नियामक
- IBBI Headquarters – New Delhi
- IBBI मुख्यालय – नई दिल्ली
- Loan becomes NPA after – 90 Days of Default
- ऋण NPA बनता है – 90 दिनों की चूक के बाद
- Banking Regulation Act – 1949
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम – 1949
- Narasimham Committee-I – 1991
- नरसिम्हम समिति-I – 1991
- Narasimham Committee-II – 1998
- नरसिम्हम समिति-II – 1998
- First Public Sector Bank of India – State Bank of India (1955)
- भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक – भारतीय स्टेट बैंक (1955)
- Banking Ombudsman Scheme – 1995
- बैंकिंग लोकपाल योजना – 1995

---

**Ques: StAR NPS, launched to simplify subscriber registration for the National Pension System (NPS), has been launched by which organization?**

**प्रश्न: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के लिए सब्सक्राइबर पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु लॉन्च किया गया StAR NPS किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है?**

- A) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / सिक्क्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI)
- B) Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) / इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI)
- C) Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) / पेंशन फंड

रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA)

D) Reserve Bank of India (RBI) / रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)

E) National Payments Corporation of India (NPCI) / नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)

**Answer: Option C**

---

### Explanation | व्याख्या:

- StAR NPS has been launched by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
- StAR NPS को Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) द्वारा लॉन्च किया गया है।
- The platform has been developed by BSE Technologies Private Limited (BTPL).
- इस प्लेटफॉर्म का विकास BSE Technologies Private Limited (BTPL) द्वारा किया गया है।
- Its objective is to streamline and simplify the subscriber registration process for the National Pension System (NPS).
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के लिए सब्सक्राइबर पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना है।
- Individuals between the ages of 18 and 85 years can use the platform.
- 18 से 85 वर्ष की आयु के व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।
- The first service offered by StAR NPS is the digital registration of new NPS accounts.
- StAR NPS की पहली सेवा नए NPS खातों का डिजिटल पंजीकरण है।
- The second service enables users to make their initial contribution while opening the account.
- दूसरी सेवा खाता खोलते समय प्रारंभिक अंशदान (Initial Contribution) करने की सुविधा प्रदान करती है।
- The third service allows subscribers to continue making future contributions after account activation.
- तीसरी सेवा खाते के सक्रिय होने के बाद भविष्य में भी अंशदान जारी रखने की सुविधा देती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- PFRDA Full Form – Pension Fund Regulatory and Development Authority
- PFRDA का पूर्ण रूप – पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण
- Established – 2003
- स्थापना – 2003
- Headquarters – New Delhi
- मुख्यालय – नई दिल्ली
- Chairman – Sivasubramanian Ramann
- अध्यक्ष – शिवसुब्रमणियन रामन्न

---

**Ques: RBI has announced a concessional USD-INR swap facility at 1.5% per annum for which category of borrowings?**

**प्रश्न: RBI ने 1.5% वार्षिक की रियायती USD-INR स्वैप सुविधा किस प्रकार की उधारी के लिए घोषित की है?**

- A) Masala Bonds / मसाला बॉन्ड
- B) FCNR(B) Deposits / एफसीएनआर(बी) जमा
- C) External Commercial Borrowings (ECBs) / बाह्य वाणिज्यिक उधारी
- D) Sovereign Gold Bonds / सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
- E) Treasury Bills / ट्रेजरी बिल

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) introduced two special USD-INR forex swap facilities to boost forex liquidity and support the rupee.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा तरलता बढ़ाने और रुपये को समर्थन देने के लिए दो विशेष USD-INR फॉरेक्स स्वैप सुविधाएँ शुरू की हैं।
- Under the FCNR(B) Deposit Window, RBI will absorb the entire hedging cost on fresh FCNR(B) deposits mobilised between June 8 and September 30, 2026.
- FCNR(B) जमा विंडो के तहत RBI 8 जून से 30 सितंबर 2026 के बीच जुटाई गई नई FCNR(B) जमाओं की पूरी हेजिंग लागत वहन करेगा।
- Eligible FCNR(B) deposits must have a minimum tenure of 3 years and a maximum tenure of 5 years.

- पात्र FCNR(B) जमाओं की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
- Fresh FCNR(B) deposits mobilised under the scheme will be exempt from CRR and SLR requirements.
- इस योजना के तहत जुटाई गई नई FCNR(B) जमाओं को CRR और SLR की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
- The ECB/OFCB Swap Window is available for Public Sector Undertakings (PSUs) and Authorised Dealer Category-I Banks raising overseas borrowings with a minimum maturity of 3 years.
- ECB/OFCB स्वैप विंडो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और अधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों के लिए उपलब्ध है, जिनकी विदेशी उधारी की न्यूनतम परिपक्वता 3 वर्ष है।
- RBI will provide the ECB swap facility at a concessional fixed cost of 1.5% per annum (compounded semi-annually).
- RBI ECB स्वैप सुविधा 1.5% वार्षिक (अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि) की रियायती निश्चित लागत पर प्रदान करेगा।
- The ECB/OFCB swap window will remain open until January 15, 2027.
- ECB/OFCB स्वैप विंडो 15 जनवरी 2027 तक खुली रहेगी।

### Static GK | स्थैतिक जीके

- RBI Established – 1 April 1935
- RBI स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- RBI Nationalised – 1 January 1949
- RBI का राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949
- Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- Governor – Sanjay Malhotra
- गवर्नर – संजय मल्होत्रा।

**Ques: According to the Reserve Bank of India (RBI), what was India's Current Account Surplus (CAS) during the January–March (Q4) quarter of FY 2025-26?**

**प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च (Q4) तिमाही में भारत का चालू खाता अधिशेष (CAS) कितना था?**

- A) \$5.2 billion (0.5% of GDP)
- B) \$6.4 billion (0.6% of GDP)
- C) \$7.1 billion (0.7% of GDP)

- D) \$8.3 billion (0.8% of GDP)
- E) \$9.5 billion (0.9% of GDP)

**Answer: Option C**

---

### Explanation | व्याख्या:

- According to the Reserve Bank of India (RBI), India recorded a Current Account Surplus (CAS) of \$7.1 billion, equivalent to 0.7% of GDP, during the January–March (Q4) quarter of FY 2025-26.
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी–मार्च (Q4) तिमाही में भारत ने \$7.1 बिलियन का चालू खाता अधिशेष (CAS) दर्ज किया, जो GDP का 0.7% था।
  - A Current Account Surplus occurs when a country's earnings from exports, services, and remittances exceed its payments for imports and other external obligations.
  - चालू खाता अधिशेष तब होता है जब किसी देश की निर्यात, सेवाओं और प्रेषण (Remittances) से होने वाली आय उसके आयात और अन्य बाह्य भुगतानों से अधिक होती है।
  - Despite the surplus in the fourth quarter, India recorded a Current Account Deficit (CAD) of \$25.2 billion for the full FY 2025-26.
  - चौथी तिमाही में अधिशेष दर्ज होने के बावजूद, पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने \$25.2 बिलियन का चालू खाता घाटा (CAD) दर्ज किया।
  - The annual CAD amounted to 0.6% of GDP.
  - वार्षिक CAD GDP का 0.6% रहा।
  - In comparison, India's Current Account Deficit in FY 2024-25 stood at \$22.9 billion.
  - तुलना के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चालू खाता घाटा \$22.9 बिलियन था।
  - The current account is a key component of the Balance of Payments (BoP) and reflects a country's transactions with the rest of the world.
  - चालू खाता, भुगतान संतुलन (BoP) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह विश्व के अन्य देशों के साथ किसी देश के आर्थिक लेनदेन को दर्शाता है।
-

**Ques: According to recent economic indicators, India is currently the world's largest market in which of the following sectors?**

**प्रश्न: हालिया आर्थिक संकेतकों के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा बाजार है?**

- A) Automobile Exports / ऑटोमोबाइल निर्यात
- B) Real-Time Digital Payments / रियल-टाइम डिजिटल भुगतान
- C) Semiconductor Manufacturing / सेमीकंडक्टर निर्माण
- D) Aircraft Manufacturing / विमान निर्माण
- E) Crude Oil Production / कच्चा तेल उत्पादन

**Answer: Option B**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- India continues to be the world's fastest-growing major economy for four consecutive years.
- भारत लगातार चार वर्षों से विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
- India has become the world's largest real-time digital payments market, driven by UPI and digital financial inclusion.
- UPI और डिजिटल वित्तीय समावेशन के कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा रियल-टाइम डिजिटल भुगतान बाजार बन गया है।
- India is the world's largest recipient of remittances and the second-largest contributor to global GDP growth.
- भारत विश्व में सर्वाधिक प्रेषण (Remittances) प्राप्त करने वाला देश तथा वैश्विक GDP वृद्धि में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
- India is the world's second-largest mobile phone manufacturer.
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है।
- India is the third-largest economy in the world on the basis of Purchasing Power Parity (PPP).
- क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

है।

- India is also the world's third-largest pharmaceutical manufacturer.
- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि निर्माता भी है।

### Static GK | स्थैतिक जीके

- India's GDP Rank (Nominal) – 6th Largest in the World
- नाममात्र GDP के आधार पर भारत – विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- India's GDP Rank (PPP) – 3rd Largest in the World
- PPP के आधार पर भारत – विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- Central Bank – Reserve Bank of India (RBI)
- केंद्रीय बैंक – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
- RBI Established – 1 April 1935
- RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- NITI Aayog CEO – Nidhi Chhibber
- नीति आयोग के CEO – निधि छिबबर
- UPI Launched – 2016
- UPI की शुरुआत – 2016
- UPI Developed By – National Payments Corporation of India (NPCI)
- UPI का विकास – नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)
- India is the world's largest real-time digital payments market.
- भारत विश्व का सबसे बड़ा रियल-टाइम डिजिटल भुगतान बाजार है।

---

**Ques: According to the S&P Global Market Intelligence report, which Indian bank recorded the highest leverage ratio among Asia-Pacific lenders with assets exceeding \$100 billion?**

**प्रश्न: S&P Global Market Intelligence की रिपोर्ट के अनुसार, 100 बिलियन डॉलर से अधिक परिसंपत्तियों वाले एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बैंकों में किस भारतीय बैंक ने सबसे अधिक लीवरेज अनुपात दर्ज किया?**

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

- C) Axis Bank / एक्सिस बैंक  
D) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक  
E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**Answer: Option D**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- According to the S&P Global Market Intelligence report, Kotak Mahindra Bank recorded the highest leverage ratio among Asia-Pacific lenders with assets exceeding \$100 billion.
- S&P Global Market Intelligence की रिपोर्ट के अनुसार, Kotak Mahindra Bank ने 100 बिलियन डॉलर से अधिक परिसंपत्तियों वाले एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बैंकों में सबसे अधिक लीवरेज अनुपात दर्ज किया।
- Kotak Mahindra Bank reported a leverage ratio of 16.56%, making it the best-capitalised lender in the region.
- कोटक महिंद्रा बैंक का लीवरेज अनुपात 16.56% रहा, जिससे यह क्षेत्र का सबसे बेहतर पूंजीकृत (Best-Capitalised) बैंक बन गया।
- Other Indian private sector banks also performed strongly in the rankings.
- अन्य भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों ने भी इस रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
- HDFC Bank recorded a leverage ratio of 11.14%, ICICI Bank 10.84%, and Axis Bank 9.28%.
- एचडीएफसी बैंक का लीवरेज अनुपात 11.14%, आईसीआईसीआई बैंक का 10.84% तथा एक्सिस बैंक का 9.28% रहा।
- Among public sector banks, Union Bank of India registered the largest year-on-year increase in leverage ratio.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में Union Bank of India ने लीवरेज अनुपात में वर्ष-दर-वर्ष सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की।
- Union Bank of India's leverage ratio increased by 69 basis points to reach 7.72%, reflecting improved capital strength.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लीवरेज अनुपात 69 बेसिस पॉइंट बढ़कर 7.72% हो गया, जो इसकी पूंजीगत मजबूती को दर्शाता है।
- The report noted that major Australian lenders such as National Australia

Bank, Australia and New Zealand Banking Group, and Commonwealth Bank of Australia reported leverage ratios below 5%.

- रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बैंक जैसे नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप और कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का लीवरेज अनुपात 5% से कम रहा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Leverage Ratio – A measure of a bank's capital relative to its total assets and exposures.
- लीवरेज अनुपात – बैंक की पूंजी और उसकी कुल परिसंपत्तियों/जोखिमों के बीच संबंध को मापने वाला संकेतक।
- Bank Capitalisation – The amount of capital maintained by a bank relative to its assets and risks.
- बैंक पूंजीकरण – बैंक द्वारा अपनी परिसंपत्तियों और जोखिमों के मुकाबले बनाए रखी गई पूंजी की मात्रा।
- Highest Leverage Ratio in Report – Kotak Mahindra Bank (16.56%)
- रिपोर्ट में सर्वाधिक लीवरेज अनुपात – कोटक महिंद्रा बैंक (16.56%)
- Largest Improvement Among PSBs – Union Bank of India (7.72%, up 69 basis points)
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक सुधार – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (7.72%, 69 बेसिस पॉइंट की वृद्धि)
- Headquarters of S&P Global – New York City, United States
- S&P Global का मुख्यालय – न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका।

**Ques: SoftBank Group recently sold a 3.25% stake in which company through an open market transaction worth ₹2,873.3 crore?**

**प्रश्न: सॉफ्टबैंक ग्रुप ने हाल ही में ₹2,873.3 करोड़ के ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के माध्यम से किस कंपनी में 3.25% हिस्सेदारी बेची?**

A) Nykaa / नायका

- B) Lenskart Solutions / लेंसकार्ट सॉल्यूशंस
- C) Zomato / ज़ोमैटो
- D) Policybazaar / पॉलिसीबाजार
- E) Paytm / पेटीएम

**Answer: Option B**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- Technology investment giant SoftBank Group sold a 3.25% stake in Lenskart Solutions through an open market transaction worth ₹2,873.3 crore.
- प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सॉफ्टबैंक ग्रुप ने ₹2,873.3 करोड़ के ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के माध्यम से लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में 3.25% हिस्सेदारी बेची।
- The stake sale was carried out by SoftBank's affiliate SVF II Lightbulb (Cayman) Ltd.
- यह हिस्सेदारी बिक्री सॉफ्टबैंक की सहयोगी कंपनी SVF II Lightbulb (Cayman) Ltd. द्वारा की गई।
- Following the transaction, SoftBank's shareholding in Lenskart declined from 13.13% to 9.88%.
- इस लेनदेन के बाद लेंसकार्ट में सॉफ्टबैंक की हिस्सेदारी 13.13% से घटकर 9.88% रह गई।
- The transaction was executed through the open market route.
- यह लेनदेन ओपन मार्केट मार्ग के माध्यम से संपन्न किया गया।
- Lenskart is one of India's leading eyewear companies, offering eyeglasses, sunglasses, contact lenses, and related vision-care products.
- लेंसकार्ट भारत की अग्रणी आईवियर कंपनियों में से एक है, जो चश्मे, सनग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस तथा अन्य विज़न-केयर उत्पाद प्रदान करती है।
- SoftBank has been one of the major investors in Lenskart and several other Indian technology-driven startups.
- सॉफ्टबैंक लेंसकार्ट सहित भारत के कई प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्टअप्स में प्रमुख निवेशकों में से एक रहा है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Lenskart Founded – 2010
- लेंसकार्ट की स्थापना – 2010
- Founders – Peyush Bansal, Amit Chaudhary, Sumeet Kapahi
- संस्थापक – पेयूष बंसल, अमित चौधरी एवं सुमीत कपाही
- Headquarters – Gurugram, Haryana
- मुख्यालय – गुरुग्राम, हरियाणा
- SoftBank Group Headquarters – Tokyo, Japan
- सॉफ्टबैंक ग्रुप मुख्यालय – टोक्यो, जापान
- Founder & CEO of SoftBank Group – Masayoshi Son
- सॉफ्टबैंक ग्रुप के संस्थापक एवं CEO – मासायोशी सोन

---

**Ques: Under RBI's new lending norms, banks can lend only to which type of REITs and InvITs?**

**प्रश्न: आरबीआई के नए ऋण नियमों के अनुसार, बैंक केवल किस प्रकार के REITs और InvITs को ऋण दे सकते हैं?**

- A) All registered trusts / सभी पंजीकृत ट्रस्ट
- B) Government-owned trusts / सरकारी स्वामित्व वाले ट्रस्ट
- C) SEBI-registered and listed trusts / SEBI में पंजीकृत एवं सूचीबद्ध ट्रस्ट
- D) Foreign investment trusts / विदेशी निवेश ट्रस्ट
- E) Unlisted trusts / गैर-सूचीबद्ध ट्रस्ट

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- Under RBI's new regulations, banks can lend only to SEBI-registered and listed REITs and InvITs.
- आरबीआई के नए नियमों के तहत बैंक केवल SEBI में पंजीकृत और सूचीबद्ध REITs

तथा InvITs को ही ऋण दे सकेंगे।

- A REIT/InvIT must have at least 80% of its underlying assets generating positive operational cash flows for a minimum period of one year.
- किसी REIT/InvIT की कम-से-कम 80% आधारभूत परिसंपत्तियाँ न्यूनतम एक वर्ष तक परिचालन से सकारात्मक नकदी प्रवाह उत्पन्न कर रही हों, तभी उसे ऋण मिलेगा।
- Banks cannot use such lending for non-permitted or speculative purposes such as land acquisition.
- इस प्रकार के ऋण का उपयोग भूमि अधिग्रहण जैसे गैर-अनुमत या सट्टात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकेगा।
- The aggregate exposure of a bank to a REIT/InvIT, along with its SPVs/Holding Companies, cannot exceed 49% of the trust's total asset value.
- किसी बैंक का REIT/InvIT तथा उसकी SPVs/होल्डिंग कंपनियों के प्रति कुल ऋण जोखिम ट्रस्ट की कुल परिसंपत्ति मूल्य के 49% से अधिक नहीं हो सकता।
- The guidelines will come into effect from **1 October 2026**.
- ये दिशानिर्देश **1 अक्टूबर 2026** से प्रभावी होंगे।
- Exposure to REITs will attract a risk weight of **100%**, while capital market exposures will carry a **125% risk weight**.
- REITs के प्रति एक्सपोजर पर **100% जोखिम भार** लागू होगा, जबकि पूंजी बाजार श्रेणी में आने वाले एक्सपोजर पर **125% जोखिम भार** लागू होगा।
- The new framework aims to strengthen prudential lending standards, improve transparency and reduce risks in bank lending to investment trusts.
- नया ढांचा विवेकपूर्ण ऋण मानकों को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा निवेश ट्रस्टों को दिए जाने वाले बैंक ऋण के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से लाया गया है।

### Static GK | स्थैतिक जीके

- RBI Established – 1 April 1935
- आरबीआई की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- RBI Nationalised – 1 January 1949
- आरबीआई का राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- Governor – Sanjay Malhotra
- गवर्नर – संजय मल्होत्रा

- First Governor – Sir Osborne Smith
  - प्रथम गवर्नर – सर ऑसबोर्न स्मिथ
  - First Indian Governor – C. D. Deshmukh
  - प्रथम भारतीय गवर्नर – सी. डी. देशमुख
- 

**Ques: Which company has received approval from the Competition Commission of India (CCI) for Sanlam Group's acquisition of a stake through a preferential issue of shares?**

**प्रश्न: सानलम ग्रुप द्वारा प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने के माध्यम से हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए CCI ने किस कंपनी में निवेश को मंजूरी दी है?**

- A) HDFC Life Insurance Company Ltd. / एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- B) ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- C) SBI Life Insurance Company Ltd. / एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- D) Shriram Life Insurance Company Ltd. / श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- E) Max Life Insurance Company Ltd. / मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

**Answer: Option D**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The Competition Commission of India (CCI) has approved a proposal by South Africa-based Sanlam Group to acquire a stake in Shriram Life Insurance Company Ltd.
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने दक्षिण अफ्रीका स्थित सानलम ग्रुप के श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में हिस्सेदारी अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- Sanlam Emerging Markets (Mauritius) Ltd. (SEMM) will acquire a 2.80% stake in the expanded equity capital of Shriram Life Insurance Company Ltd.
- सानलम इमर्जिंग मार्केट्स (मॉरीशस) लिमिटेड (SEMM) श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस

कंपनी लिमिटेड की विस्तारित इक्विटी पूंजी में 2.80% हिस्सेदारी प्राप्त करेगी।

- The acquisition will be carried out through a Preferential Issue of Shares.
- यह अधिग्रहण प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने (Preferential Issue of Shares) के माध्यम से किया जाएगा।
- The approval reflects CCI's role in examining mergers, acquisitions, and combinations to ensure fair competition in the market.
- यह मंजूरी बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु विलय, अधिग्रहण और संयोजनों की जांच में CCI की भूमिका को दर्शाती है।
- Sanlam Group is one of the leading financial services groups headquartered in South Africa.
- सानलम ग्रुप दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनियों में से एक है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Competition Commission of India (CCI) Formed – 14 October 2003
  - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का गठन – 14 अक्टूबर 2003
  - Headquarters – New Delhi
  - मुख्यालय – नई दिल्ली
  - Chairperson – Ravneet Kaur
  - अध्यक्ष – रवनीत कौर
  - Parent Ministry – Ministry of Corporate Affairs
  - मूल मंत्रालय – कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
  - Competition Act Enforced – 2002
  - प्रतिस्पर्धा अधिनियम – 2002
  - Sanlam Group Headquarters – Cape Town
  - सानलम ग्रुप मुख्यालय – केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका
  - Shriram Life Insurance Company Ltd. Headquarters – Hyderabad
  - श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय – हैदराबाद, तेलंगाना
  - Acquisition Stake Approved – 2.80% of expanded equity capital through preferential issue.
  - स्वीकृत हिस्सेदारी – विस्तारित इक्विटी पूंजी का 2.80%, प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने के माध्यम से।
-

**Ques: What was the theme of the 11th Governing Council Meeting of NITI Aayog?**

**प्रश्न: नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की थीम क्या थी?**

- A) Sabka Saath Sabka Vikas / सबका साथ, सबका विकास
- B) Digital India for New India / डिजिटल इंडिया फॉर न्यू इंडिया
- C) Inclusive Human Development for Viksit Bharat@2047 / विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास
- D) Atmanirbhar Bharat through Innovation / नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत
- E) Green Growth for Sustainable Future / सतत भविष्य हेतु हरित विकास

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The 11th Governing Council Meeting of NITI Aayog was held at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi.
- नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में किया गया।
- The theme of the meeting was **"Inclusive Human Development for Viksit Bharat@2047."**
- बैठक की थीम "विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास" थी।
- Prime Minister Narendra Modi chaired the meeting.
- बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
- Chief Ministers, Lieutenant Governors and Administrators representing 28 States and 5 Union Territories participated in the meeting.
- बैठक में 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल एवं प्रशासकों ने भाग लिया।
- The Prime Minister emphasized the importance of **cooperative federalism** for achieving the vision of Viksit Bharat@2047.

- प्रधानमंत्री ने विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **सहकारी संघवाद** के महत्व पर बल दिया।
- He called upon States to increase the number of **Lakhpati Didis** from 3 crore to 6 crore.
- उन्होंने राज्यों से **लखपति दीदियों** की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने का आह्वान किया।
- The Prime Minister stressed the importance of **One District One Product (ODOP)** and export-oriented development strategies.
- प्रधानमंत्री ने **वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP)** तथा निर्यातोन्मुख विकास रणनीतियों के महत्व पर बल दिया।
- States were advised to tackle challenges such as **drug abuse and cyber fraud** through awareness and preventive measures.
- राज्यों को **नशा दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी** जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु जागरूकता एवं निवारक उपाय अपनाने की सलाह दी गई।
- He highlighted the need for district-level monitoring and focused 100-day and five-year targets for achieving Viksit Bharat@2047.
- उन्होंने विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिला-स्तरीय निगरानी तथा 100-दिवसीय एवं 5-वर्षीय लक्ष्यों पर विशेष जोर दिया।

#### Static Facts | स्थिर तथ्य

- **NITI Aayog Established – 1 January 2015**
- **नीति आयोग की स्थापना – 1 जनवरी 2015**
- **Headquarters – New Delhi**
- **मुख्यालय – नई दिल्ली**
- **Chairperson – Prime Minister Narendra Modi**
- **अध्यक्ष – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी**
- **Vice Chairperson – Ashok Kumar Lahiri**
- **उपाध्यक्ष – अशोक कुमार लाहिड़ी**
- **CEO – Nidhi Chhibber**
- **सीईओ – निधि छिब्बर**
- **Replaced Institution – Planning Commission**
- **प्रतिस्थापित संस्था – योजना आयोग**

---

**Ques: Reliance Industries Limited (RIL) recently raised JPY 91.9 billion (approximately USD 625 million) through which type of loan?**

**प्रश्न: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) ने हाल ही में JPY 91.9 बिलियन (लगभग USD 625 मिलियन) किस प्रकार के ऋण के माध्यम से जुटाए?**

- A) Samurai Loan / समुराई ऋण
- B) Syndicated Loan / सिंडिकेटेड ऋण
- C) Masala Loan / मसाला ऋण
- D) Green Bond / ग्रीन बॉन्ड
- E) External Commercial Borrowing / बाह्य वाणिज्यिक उधारी

**Answer: Option A**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- Reliance Industries Limited (RIL) raised JPY 91.9 billion (approximately USD 625 million) through a Samurai Loan.
- रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) ने समुराई ऋण (Samurai Loan) के माध्यम से JPY 91.9 बिलियन (लगभग USD 625 मिलियन) जुटाए।
- This is the largest Samurai Loan ever raised by an Indian corporate.
- यह किसी भारतीय कंपनी द्वारा जुटाया गया अब तक का सबसे बड़ा समुराई ऋण है।
- It is also the third-largest Samurai borrowing by an Asian corporate.
- यह किसी एशियाई कंपनी द्वारा लिया गया तीसरा सबसे बड़ा समुराई ऋण भी है।
- A Samurai Loan is a Japanese Yen-denominated cross-border syndicated loan provided by Japanese lenders to a non-Japanese borrower.
- समुराई ऋण जापानी येन में दिया जाने वाला सीमा-पार सिंडिकेटेड ऋण होता है, जो जापानी ऋणदाताओं द्वारा किसी गैर-जापानी उधारकर्ता को प्रदान किया जाता है।
- The transaction involved participation from 10 Japanese and Taiwanese banks.
- इस लेनदेन में 10 जापानी और ताइवानी बैंकों ने भाग लिया।
- RIL also secured USD 600 million equivalent financing through untied

facilities backed by Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), Japan's export credit agency.

- RIL ने जापान की निर्यात ऋण एजेंसी NEXI द्वारा समर्थित सुविधाओं के माध्यम से USD 600 मिलियन समतुल्य वित्तपोषण भी प्राप्त किया।
- The NEXI-backed financing will be used for solar photovoltaic (PV) projects and battery giga factories.
- NEXI समर्थित वित्तपोषण का उपयोग सौर फोटोवोल्टिक (PV) परियोजनाओं और बैटरी गीगा फैक्ट्रियों के लिए किया जाएगा।
- Additionally, RIL secured nearly USD 500 million equivalent financing through facilities supported by Korea Trade Insurance Corporation (KSURE), South Korea's export credit agency.
- इसके अतिरिक्त, RIL ने दक्षिण कोरिया की निर्यात ऋण एजेंसी KSURE द्वारा समर्थित सुविधाओं के माध्यम से लगभग USD 500 मिलियन समतुल्य वित्तपोषण भी प्राप्त किया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Reliance Industries Limited (RIL) Headquarters – Mumbai
- रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- Chairman & Managing Director – Mukesh Ambani
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – मुकेश अंबानी
- NEXI Full Form – Nippon Export and Investment Insurance
- NEXI का पूर्ण रूप – निप्पोन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस
- NEXI Country – Japan
- NEXI का देश – जापान
- KSURE Full Form – Korea Trade Insurance Corporation
- KSURE का पूर्ण रूप – कोरिया ट्रेड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
- KSURE Country – South Korea
- KSURE का देश – दक्षिण कोरिया
- Currency of Japan – Japanese Yen (JPY)
- जापान की मुद्रा – जापानी येन (JPY)

---

**Ques : The newly launched cross-border remittance mechanism links India's**

### UPI with which country's payment interface?

प्रश्न: हाल ही में शुरू की गई सीमा-पार प्रेषण प्रणाली भारत के UPI को किस देश की भुगतान प्रणाली से जोड़ती है?

- A. Bhutan / भूटान
- B. Bangladesh / बांग्लादेश
- C. Sri Lanka / श्रीलंका
- D. Nepal / नेपाल
- E. Maldives / मालदीव

**Answer: Option D**

---

#### Explanation | व्याख्या:

- India and Nepal have launched a peer-to-peer (P2P) cross-border remittance mechanism.
- भारत और नेपाल ने पीयर-टू-पीयर (P2P) सीमा-पार प्रेषण प्रणाली शुरू की है।
- The initiative establishes a direct linkage between India's Unified Payments Interface (UPI) and Nepal's National Payments Interface (NPI).
- यह पहल भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (NPI) के बीच सीधा संपर्क स्थापित करती है।
- The system enables seamless, secure and real-time money transfers between citizens of both countries.
- यह प्रणाली दोनों देशों के नागरिकों को निर्बाध, सुरक्षित एवं वास्तविक समय में धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।
- Users can send and receive money directly through mobile banking applications and digital wallets.
- उपयोगकर्ता मोबाइल बैंकिंग ऐप्स और डिजिटल वॉलेट्स के माध्यम से सीधे धन भेज और प्राप्त कर सकते हैं।
- The UPI-NPI integration strengthens bilateral digital financial connectivity between India and Nepal.
- UPI-NPI एकीकरण भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय डिजिटल वित्तीय संपर्क को मजबूत करता है।

- The initiative promotes financial inclusion and affordable cross-border payment services.
- यह पहल वित्तीय समावेशन और किफायती सीमा-पार भुगतान सेवाओं को बढ़ावा देती है।
- The mechanism facilitates faster settlements and improves the ease of remittances for individuals and businesses.
- यह प्रणाली तेज़ भुगतान निपटान सुनिश्चित करती है तथा व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए प्रेषण को अधिक सरल बनाती है।
- The initiative is expected to boost tourism, trade and economic cooperation between the two neighbouring countries.
- यह पहल दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

#### Static Facts | स्थैतिक तथ्य

- UPI Launched – 11 April 2016
- यूपीआई की शुरुआत – 11 अप्रैल 2016
- Developed By – National Payments Corporation of India (NPCI)
- विकसितकर्ता – नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)
- NPCI Established – 2008
- एनपीसीआई की स्थापना – 2008
- Headquarters (NPCI) – Mumbai, Maharashtra
- एनपीसीआई मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- Currency of Nepal – Nepalese Rupee (NPR)
- नेपाल की मुद्रा – नेपाली रुपया (NPR)
- Capital of Nepal – Kathmandu
- नेपाल की राजधानी – काठमांडू

**Ques: To what percentage has Axis Bank increased its stake in Axis Max Life Insurance after making an additional investment of up to ₹380 crore?**

**प्रश्न: ₹380 करोड़ तक का अतिरिक्त निवेश करने के बाद एक्सिस बैंक ने Axis Max Life Insurance में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर ली है?**

A) 18.99%

- B) 19.02%
- C) 19.50%
- D) 19.99%
- E) 20.50%

**Answer: Option D**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- Axis Bank has increased its stake in Axis Max Life Insurance to 19.99%.
- एक्सिस बैंक ने Axis Max Life Insurance में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 19.99% कर ली है।
- The bank made an additional investment of up to ₹380 crore for this stake enhancement.
- बैंक ने हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ₹380 करोड़ तक का अतिरिक्त निवेश किया है।
- Earlier, Axis Bank's shareholding in Axis Max Life Insurance stood at 19.02%.
- इससे पहले Axis Max Life Insurance में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी 19.02% थी।
- The shareholding includes Axis Bank and its subsidiaries, Axis Securities Ltd. and Axis Capital Ltd.
- इस हिस्सेदारी में एक्सिस बैंक के साथ-साथ उसकी सहायक कंपनियाँ Axis Securities Ltd. और Axis Capital Ltd. भी शामिल हैं।
- The investment strengthens Axis Bank's strategic partnership in the life insurance business.
- यह निवेश जीवन बीमा क्षेत्र में एक्सिस बैंक की रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करता है।

**Static Part | स्थैतिक जानकारी:**

- Axis Bank Founded – 3 December 1993
- एक्सिस बैंक की स्थापना – 3 दिसंबर 1993
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- MD & CEO – Amitabh Chaudhry
- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी – अमिताभ चौधरी

- Chairperson – P N Prasad
- अध्यक्ष – पी. एन. प्रसाद

---

**Ques : What is the objective of the newly released BIS standard IS 20201:2026?**

**प्रश्न: हाल ही में जारी BIS मानक IS 20201:2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?**

- A. To promote export of hybrid seeds / संकर बीजों के निर्यात को बढ़ावा देना
- B. To regulate fertilizer pricing / उर्वरकों की कीमतों को विनियमित करना
- C. To provide a management framework for Community Seed Banks and conserve indigenous crop varieties / सामुदायिक बीज बैंकों के लिए प्रबंधन ढांचा प्रदान करना तथा स्वदेशी फसल किस्मों का संरक्षण करना
- D. To increase pesticide production / कीटनाशक उत्पादन बढ़ाना
- E. To promote genetically modified crops / आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों को बढ़ावा देना

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The Bureau of Indian Standards (BIS) has released a new Indian Standard – IS 20201:2026 Community Seed Bank Management – Requirements.
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने नया भारतीय मानक IS 20201:2026 – कम्युनिटी सीड बैंक मैनेजमेंट (आवश्यकताएँ) जारी किया है।
- The standard provides a comprehensive management framework for Community Seed Banks (CSBs) across India.
- यह मानक देशभर के सामुदायिक बीज बैंकों (CSBs) के लिए एक व्यापक प्रबंधन ढांचा प्रदान करता है।
- Its primary objective is to conserve indigenous crop varieties and strengthen agricultural resilience against climate change.

- इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी फसल किस्मों का संरक्षण करना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की सहनशीलता को मजबूत बनाना है।
- Traditional seed varieties possess important traits such as drought tolerance, disease resistance and high nutritional value.
- पारंपरिक बीज किस्मों में सूखा सहनशीलता, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा उच्च पोषण मूल्य जैसे महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं।
- The standard supports the conservation of agricultural biodiversity in India.
- यह मानक भारत में कृषि जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- It aligns with Sustainable Development Goal (SDG) 2 – Zero Hunger.
- यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2 – शून्य भूख के अनुरूप है।
- The standard complements the National Food Security and Nutrition Mission (NFSNM), which provides one-time assistance of ₹50 lakh for establishing Community Seed Banks.
- यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM) का समर्थन करता है, जिसके तहत सामुदायिक बीज बैंक स्थापित करने हेतु ₹50 लाख की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।
- It covers the entire lifecycle of seed bank operations, including viability testing, documentation, quality assurance and risk management.
- यह बीज बैंक संचालन के संपूर्ण जीवनचक्र को कवर करता है, जिसमें व्यवहार्यता परीक्षण, दस्तावेजीकरण, गुणवत्ता आश्वासन तथा जोखिम प्रबंधन शामिल हैं।
- The draft standard was developed under the convenorship of ICAR–National Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR).
- इस मसौदा मानक को ICAR–राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR) के संयोजकत्व में विकसित किया गया।

#### Static Facts | स्थैतिक तथ्य

- BIS Established – 1987
- बीआईएस की स्थापना – 1987
- BIS Act, 2016 Enforced – 12 October 2017
- बीआईएस अधिनियम, 2016 लागू – 12 अक्टूबर 2017
- Headquarters – New Delhi
- मुख्यालय – नई दिल्ली
- Director General, BIS – Shri Sanjay Garg

- महानिदेशक, बीआईएस – श्री संजय गर्ग
- SDG 2 – Zero Hunger
- SDG 2 – शून्य भूख

---

**Ques: What amount of dividend cheque for FY 2025-26 was handed over by State Bank of India (SBI) to the Government of India?**

**प्रश्न: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भारत सरकार को कितने रुपये का लाभांश (Dividend) चेक सौंपा?**

- A) ₹7,813 crore / ₹7,813 करोड़
- B) ₹8,813 crore / ₹8,813 करोड़
- C) ₹9,813 crore / ₹9,813 करोड़
- D) ₹10,813 crore / ₹10,813 करोड़
- E) ₹11,813 crore / ₹11,813 करोड़

**Answer: Option B**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- State Bank of India (SBI) handed over a dividend cheque of ₹8,813 crore for the financial year 2025-26 to Union Finance Minister Nirmala Sitharaman.
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹8,813 करोड़ का लाभांश चेक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा।
- The dividend cheque was presented by SBI Chairman C. S. Setty.
- यह लाभांश चेक SBI के अध्यक्ष C. S. Setty द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- Earlier, SBI's Central Board declared a dividend of ₹17.35 per equity share for the year ended March 31, 2026.
- इससे पहले SBI के केंद्रीय बोर्ड ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए ₹17.35 प्रति इक्विटी शेयर लाभांश घोषित किया था।
- The Government of India holds approximately 55% stake in SBI, making it the largest shareholder of the bank.

- भारत सरकार के पास SBI में लगभग 55% हिस्सेदारी है, जिससे वह बैंक की सबसे बड़ी शेयरधारक है।
- SBI reported a net profit of ₹80,032 crore in FY26, registering a year-on-year growth of 12.88%.
- SBI ने FY26 में ₹80,032 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.88% की वृद्धि दर्शाता है।
- SBI's overall business crossed ₹109 trillion during FY26.
- FY26 के दौरान SBI का कुल व्यवसाय ₹109 ट्रिलियन से अधिक हो गया।
- The bank's total deposits stood at ₹59.8 trillion, while advances reached ₹49.3 trillion.
- बैंक की कुल जमा राशि ₹59.8 ट्रिलियन और कुल ऋण (Advances) ₹49.3 ट्रिलियन तक पहुंच गया।
- SBI's agriculture portfolio crossed the ₹4 trillion mark, reflecting continued growth in lending to the farm sector.
- SBI का कृषि ऋण पोर्टफोलियो ₹4 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया, जो कृषि क्षेत्र को ऋण वितरण में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।

